



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4188]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 25, 2018/कार्तिक 3, 1940

No. 4188]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2018/KARTIKA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5393(अ).**— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3093 (ई) के तहत अपर सत्र न्यायाधीश-03, नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय, को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (9) के तहत कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय अर्थात् जिला न्यायाधीश-IV सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रभारी नई दिल्ली, पुलिस जिला पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के “अपर न्यायाधीश” के रूप में नियुक्त किया था।

और जबकि, श्री सौरभ कुलश्रेष्ठ, अपर सत्र न्यायाधीश-03, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 4200 (ई) के तहत उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (9) के तहत कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 29 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 4200 (ई) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की

सिफारिश पर श्री राकेश सयाल, अपर सत्र न्यायाधीश-03, नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उक्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV(भाग-III)]

प्रवीण वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th October, 2018

**S.O. 5393(E).**— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 3093 (E) dated the 22<sup>nd</sup> September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), appointed the Additional Sessions Judge-03, New Delhi, Patiala House Court as “Additional Judge” to the National Investigation Agency Special Court i.e. the District Judge-IV-cum-Additional Sessions Judge in-charge, New Delhi Police District, Patiala House Court, New Delhi for conducting the business under sub-section (9) of section 11 of the said Act;

And whereas, Shri Saurabh Kulshreshta, Additional Sessions Judge-03, Patiala House Courts, New Delhi who was appointed as the Additional Judge to the National Investigation Agency Special Court for conducting the business under sub-section (9) of section 11 of the said Act *vide* notification number S.O. 4200 (E) dated the 29<sup>th</sup> August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and, in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 4200 (E) dated the 29<sup>th</sup> August, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Chief Justice of High Court of Delhi, hereby appoints Shri Rakesh Syal, Additional Sessions Judge-03, New Delhi, Patiala House Court as the Additional Judge to the said National Investigation Agency Special Court for the purposes of the said Act.

[F. No. 17011/50/2009/IS-IV(Part-III)]

PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.